(ग) मंत्रालय द्वारा निकट भविष्य में और किन-किन क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों को सौंपे जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) रेलों ने उनकी विभिन्न आफ-लाइन गतिविधियों का निजीकरण करने का विनिश्चय किया है, इन गतिविधियों में "अपने माल डिब्बे के मालिक बने" योजना के अंतर्गत माल डिब्बों का निजी स्वामित्व, रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यकरण/अनुरक्षण, पर्यटक गाड़ियों का स्वामित्व, विपणन और प्रबंधन आदि शामिल है, पूंजी गहन रेल परियोजनाओं के लिए निजी निवेश आकर्षित करने के लिए बनाइए, मालिक बनिए, पट्टे पर दीजिए और हस्तांतरित कीजिए" योजना भी शुरू की गई है।

(ख) "अपने माल डिब्बे के मालिक बनें" योजना के अंतर्गत चौपहियों के हिसाब से लगभग 12,000 माल डिब्बों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब तक 19 स्टेशनों पर रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यकरण/अनुरक्षण करने के बदले विज्ञापन के एकल अधिकार दिये गये हैं। बी०ओ०एल०टी० योजना के अंतर्गत शुरू की जाने वाले चार आयान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए खुली बोलियां आमंत्रित की गयी है। पर्यटक गाड़ियों के लिए प्राप्त खुली बोलियों के मूल्यांकन के आधार पर पांच पर्यटक गाड़ियां चलाने के लिए चार पार्टियों की बोलियों का चयन किया गया है।

(ग) फिलहाल कोई तत्काल प्रस्ताव नहीं है।

एशिया ब्राउन बोवेरी द्वारा विद्युत इंजनों की आपूर्ति

2584. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एशिया ब्राउन बोवेरी द्वारा किये गये करार के अनुसार 6,000 अश्वशक्ति के विद्युत चालित रेल इंजनों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो यह आपूर्ति कब तक शुरू की जाएगी और क्या रेलवे ने इन आयातित इंजनों के प्रयोग का उपयुक्त प्रबंध कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इन इंजनों का किन-किन रेलगाड़ियों में उपयोग किया जाएगा और क्या रेलवे को इन इंजनों के प्रयोगार्थ वर्तमान की तुलना में और अधिक बिजली की आवश्यकता पड़ेगी;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या एशिया ब्राउन बोवेरी के साथ हुये करार के आधार पर हमारे देश को इस इंजन से संबंधित प्रौद्योगिकी भी मिलेगी जिससे भविष्य में इन इंजनों का निर्माण देश में ही किया जाना संभव हो सकेगा; और

(च) यदि हां, तो यह प्रौद्योगिकी कब तक मिलेगी और इस प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु सरकार द्वारा देश में कौन-कौन सी कर्मशालाएं तैयार की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़): (क) और (ख) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन रेल इंजनों का लदान मई, 1995 में शुरू किया जाना है तथा अंतिम लदान नवंबर, 1996 में किया जाना है। इन रेल इंजनों का उपयोग करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।

(ग) यात्री रेल इंजनों का उपयोग राजधानी/शताब्दी गाड़ियां चलाने में तथा माल रेल इंजनों का उपयोग पूर्व तथा उत्तर रेलों पर मालगाड़ियां चलाने में किया जाएगा। इन इंजनों के उपयोग के लिए अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड़) जी हां, भारतीय रेल, इन इंजनों का भारत में निर्माण करने के लिए ए बी बी से प्रौद्योगिकी भी प्राप्त करेगी।

(च) इन रेल इंजनों के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शुरू हो चुका है तथा चि०रे०का० में इन रेल इंजनों का निर्माण किए जाने तक जारी रहेगा।

रेलगाड़ियों की गति

2585. **श्री सुशील बरोंगपा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य एशियाई देशों की रेलगाड़ियों की तुलनात्मक गतियों सहित भारत में रेलगाड़ियों की अधिकतम गति कितनी है;

(ख) हमारा देश रेलगाड़ियों की गति, दुर्घटनाओं की रोकथाम करने और रेलयात्रियों को चोरी/डकैती और लूट से सुरक्षा देने के मामले में अन्य एशियाई देशों से पीछे क्यों है; और

(ग) देश में रेल सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़): (क) म्यांमार (बर्मा), पाकिस्तान, श्रीलंका, ताइवान, थाइलैंड, जापान और चीन में क्रमशः 48 कि०प्र०घं०, 125 कि०प्र०घं० 100 कि०प्र०घं०, 130 कि०प्र०घं०, 103 कि०प्र०घं०, 240 कि०प्र०घं०, 160 कि०प्र०घं०, की गाड़ियों की अधिकतम अनुमेय गति की तुलना में भारत में गाड़ी की अधिकतम अनुमेय गति 140 कि०प्र०घं०, है।

(ख) वर्ग "क" मार्गों पर व्यवस्थित मौजूदा रेलपथ संरचना 160 कि०प्र०घं० तक की गति वहन करने में समर्थ है बशर्ते कि सिगनल प्रणालियां सशक्त बनाई जाएं। जापान की भांति गाड़ियों को उच्च गति पर चलाने के लिए पृथक समर्पित रेल लाइन की आवयकता होगी जो अत्यधिक पूंजी गहन होगा, जो फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

विभिन्न एशियाई देशों के रेल सुरक्षा परिदृश्य की तुलना करने के लिए मानकीकृत सूचना उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के जरिए भारतीय रेलों पर ऐसे अपराधों की रोकथाम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे अपराध राज्य राज्य सरकार के क्षेत्र में आते हैं क्योंकि पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है और रेलें इस बुराई पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों को अपेक्षित सहायता प्रदान करती है।

परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं जिनकी संख्या 1983-84 में 768 थी 1993-94 में कम होकर 520 रह गई है। दुर्घटनाओं के संबंध में प्राचल विभिन्न देशों में हमेशा समान नहीं होते और इसलिए संभवतः सर्वत्र लागू नहीं किए जा सकते।

(ग) गाड़ी सेवाओं में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। गाड़ी सेवाओं में सुधार करने के लिए किए गए/अथवा प्रस्तावित कुछ उपाय इस प्रकार हैं:—

(1) नई गाड़ियां चलाना, मौजूदा गाड़ियों के चालन क्षेत्र का विस्तार करना और गैर-दैनिक गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करना।

(2) गाड़ियों की गति बढ़ाना।

(3) दैनिक यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए उपनगरीय सेवाओं की संख्या में वृद्धि करना।

(4) गैर-विद्युतीकरण खंडों पर डीजल मल्टीपल यूनिट/डीजल कर्षित पुश पुल सेवाएं चलाना, गैर-उपनगरीय विद्युतीकृत खंडों पर मुख्य लाइन बिजली गाड़ियां चलाना और यातायात के कम घनत्व वाले मार्गों पर रेल बसें चलाना।

(5) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों और अन्य चुनिंदा मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूल 3-टियर शयनयान सवारी डिब्बों की व्यवस्था करना।

(6) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में चुनिंदा आधार पर विशेष किस्म के वातानुकूल 2-टियर सवारी डिब्बों (सरकने वाले दरवाजों सहित) की व्यवस्था करना।

Telephone services in superfast trains

2586. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that telephone services would be made available in the near furture in the superfast and Mail Trains in the country, in collaboration with foreign companies.

(b) if so, the details thereof; and

(c) which trains are likely to be covered in the initial stages?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) A pilot project is being undertaken to evaluate possibility through satellite communication.

(b) A memorandum of understanding has been signed by the Ministry of Communications with INMARSAT for conducting the pilot project for providing telephone communication services on fast trains. This pilot project will be conducted jointly by the Indian Railways, Videsh Sanchar Nigam Limited (VSNL) and the International Maritime Satellite Organisation (INMARSAT). Trials will be conducted with special satellite terminals to evaluate their suitability for communication from moving trains. The trials are proposed to be started as soon as the terminals are made available by INMARSAT, which are expected by June'95.

(c) The trials are proposed to be carried out on the New Delhi-Bombay Central Rajdhani Express and the Broad Guage 'Palace on Wheels' trains.